Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-I**

LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Friday, July 25, 2025 / Sravana 03, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, July 25, 2025 / Sravana 03, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

REFERENCE RE: 26TH ANNIVERSARY OF KARGIL VIJAY DIWAS	1
…	2
ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION (S.Q. NO. 81)	2A – 30
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 82 – 100)	31 – 50
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 921 – 1150)	51 – 280

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, July 25, 2025 / Sravana 3, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, July 25, 2025 / Sravana 3, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 85**
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS	**285**
22nd to 25th Reports	
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS	**286**
Statements	
BUSINESS OF THE HOUSE	**287**
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	**287**
10th Report	
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**288 - 97**
Shri Ravindra Shukla *Alias* Ravi Kishan	**288**
Shri Ashok Kumar Rawat	**288**
Shrimati Mahima Kumari Mewar	**289**
Shri Jugal Kishore	**289**
Captain Brijesh Chowta	**290**
Shri Yogender Chandolia	**290**
Shri Arun Govil	**291**
Shri Gopal Jee Thakur	**291**
Shri Manoj Tiwari	**292**
Shri Gaurav Gogoi	**292**
Shri Vamsi Krishna Gaddam	**293**

Shri V. K. Sreekandan	**293**
Shri Kodikunnil Suresh	**294**
Dr. Prashant Yadaorao Padole	**294**
Shri M. K. Raghavan	**295**
Shri Utkarsh Verma Madhur	**295**
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	**296**
Shri Arvind Ganpat Sawant	**296**
Shri Hanuman Beniwal	**297**
Shri Rajkumar Roat	**297**
….	**298 - 301**

xxx

(1100/KN/GM)
1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के बारे में उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 26 जुलाई को सम्पूर्ण राष्ट्र भारतीय सेना के अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के अमर प्रतीक कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मना रहा है।

कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में अपनी असाधारण वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और संकल्प का परिचय दिया तथा अंतत: विजय श्री प्राप्त की।

आज हम इस अवसर पर अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तथा उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होने अपने राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन हम उन शहीदों के परिवारों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

अब यह सभा कारगिल के शहीदों के सम्मान में मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

--

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने हमेशा सदन में यह प्रयास किया है कि सदन चले और विशेष रूप से प्रश्न काल के समय मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि प्रश्न काल माननीय सदस्यों का समय होता है। उसमें व्यापक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदन में नियोजित तरीके से बाधा की जाती है और तख्तियां लेकर नारेबाजी की जा रही है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है, किसी विषय पर चर्चा करनी है, तो आप मेरे पास आएं। हर विषय पर, हर मुद्दे पर सरकार से बात करके चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन हम आते ही सदन के अंदर या सदन के बाहर केवल तख्तियां लेकर नारेबाजी करें, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको लगता है तो आप मेरे पास आइए। मैं सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाता हूं और मैं आपको बुलाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा करें, विषयों पर चर्चा करें, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। हमारे पीछे 20-20 लाख लोग बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं। लोग देखते हैं कि हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर, हमारी आकांक्षाओं पर, हमारी चिंताओं पर सदन में चर्चा होगी। आप तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं। यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं? नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप आकर मुझसे मिलें। मैं हर विषय पर चर्चा के लिए आपसी सहमति बनाऊंगा, लेकिन प्रश्न काल के अंदर, किसी विषय के अंदर जिन माननीय सदस्यों का प्रश्न है, केवल उनको ही बोलने का अवसर दिया जाता है। यह अच्छी परंपरा और परिपाटी रही है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हमें प्रयास करना चाहिए कि किसी विषय पर गतिरोध हो, तो आप बात करें। यह अच्छी परंपरा और परिपाटी रही है।

… (व्यवधान)

(1105/NK/RCP)

माननीय अध्यक्ष : सदन में सरकार और प्रतिपक्ष बैठ कर चर्चा करती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप चर्चा के लिए आइए, हम हर गतिरोध को समाप्त करेंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, आपके भी प्रतिनिधि भी होंगे। अगर कुछ मुद्दों का समाधान निकलता है तो उचित है नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: लेकिन असहमति किस तरह से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरह से होनी चाहिए, संसदीय लोकतंत्र की परिपाटी और परंपरा के अनुसार होनी चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं। सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 81.

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री कीर्ति वर्धन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

(pp. 3-30)

(प्रश्न 81)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 81, श्री सुब्बारायण जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री सेल्वाराज जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री कीर्तिवर्धन जी।

… (व्यवधान)

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH: Sir, a Statement is laid on the Table of the House. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1106 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/IND/PS)

1400 hours

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1400 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

1400 hours

(At this stage, Sushri Mahua Moitra, Dr. Mallu Ravi, Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood near the Table)

… (*Interruptions*)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1401 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 2, श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव।

… (व्यवधान)

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Medical Commission, New Delhi, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Medical Commission, New Delhi, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Gurgaon, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Gurgaon, for the year 2018-2019, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Hindustan Antibiotics Limited, Pune, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) Three Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) A copy of the Drugs and Cosmetics (Compounding of Offences) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 259(E) in Gazette of India dated 25th April, 2025 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 18 of the Pharmacy Act, 1948:-

(i) The Pharmacy Practice (Amendment) Regulations, 2025 published in Notification No. 14-148/2024-PCI in Gazette of India dated 3rd April, 2025.

(ii) The Pharmacy Council of India (Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Regulations, 2025 published in Notification No. 19-1/2025-PCI in Gazette of India dated 13th June, 2025.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Seaman's Provident Fund Organisation (Navik Bhavishya Nidhi), Mumbai, for the year 2023-2024, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seaman's Provident Fund Organisation (Navik Bhavishya Nidhi), Mumbai, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 395(E) in Gazette of India dated 18th June, 2025 under Section 51 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021.

… (*Interruptions*)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर) : माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

(1) (एक) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

लोक लेखा समिति
22वां से 25वां प्रतिवेदन

1403 बजे

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं लोक लेखा समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) 'सीएमपीएफओ प्रबंधन द्वारा दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के डिबंचर को भुनाने के लिए समय पर निर्णय लेने में विफलता के परिणामस्वरूप 315.35 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि' विषय के बारे में बाईसवां प्रतिवेदन।

(2) 'भूमि अधिग्रहण के मामले में रेल प्रशासन की अनिर्णयता के कारण हानि : पूर्व मध्य रेलवे' के बारे में लोक लेखा समिति के 97वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(3) 'फार्म-'एफ' में घोषणा के समर्थन के बिना छूट प्रदान करना' के बारे में लोक लेखा समिति के 136वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

(4) 'बिक्री के दमन के कारण करापवंचन' के बारे में लोक लेखा समिति के 138वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंच्चीसवां प्रतिवेदन।

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

Statements

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Hon. Chairperson, Sir, I rise to lay on the Table the following statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs:-

(1) The Statement showing Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the First Report of the Committee on External Affairs (Eighteenth Lok Sabha) on action taken on the Recommendations contained in the Twenty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on the subject "India and Gulf Cooperation Council (GCC) - Contours of Cooperation".

(2) The Statement showing Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Second Report of the Committee on External Affairs (Eighteenth Lok Sabha) on action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-seventh Report (Seventeenth Lok Sabha) on the subject "India's Engagement with G20 Countries".

(3) The Statement showing Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Third Report of the Committee on External Affairs (Eighteenth Lok Sabha) on action taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) on the Subject "Countering Global Terrorism at Regional and International Levels".

HON. CHAIRPERSON: Mr. Arvind Sawant or any other Member of Parliament is your colleague. You should allow an hon. Member to present a Report.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Arjun Ram Meghwal ji.

Item No. 8.

… (*Interruptions*)

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 28th of July, 2025, will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains – (i) Further consideration and passing of the Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024; and (ii) Consideration and passing of the Merchant Shipping Bill, 2024].
2. Consideration and passing of the following Bills:-

   (i) The Indian Ports Bill, 2025;

   (ii) The National Sports Governance Bill, 2025; and

   (iii) The National Anti-Doping (Amendment) Bill, 2025

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Item no. 8A.

Shri Arjun Ram Meghwal ji.

… (*Interruptions*)

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
10th Report

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I rise to present the Tenth Report of the Business Advisory Committee.

… (*Interruptions*)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनके भी नियम 377 के अधीन मामले हैं और जिन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, वे मामले के पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

Re: Need to establish an Indian Institute of Technology in Gorakhpur, Uttar Pradesh

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : गोरखपुर उ० प्र० पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है । गोरखपुर शिक्षा ,व्यापार और पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है । पूर्वांचल और बिहार के लगभग 20 ज़िले अपने विभिन्न ज़रूरतों के लिए गोरखपुर पर निर्भर है । यहाँ रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क और एयरपोर्ट भी है । गोरखपुर के आस पास के ज़िलों के छात्र बड़े मेधावी हैं। उनमें अपार संभावनाएँ हैं , वो गोरखपुर में IIT की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आई आई टी न होने के कारण उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर , दलित और वंचित वर्ग के छात्र संसाधनों की कमी के कारण अपने सपने को अधूरा छोड़ देते हैं। गोरखपुर में एक IIT की स्थापना हो जाने से यहाँ के छात्र - छात्राओं को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा। गोरखपुर में IIT की स्थापना के लिए जो भी सहायता चाहिए उसे राज्य सरकार उपलब्ध्ध कराने के लिए तत्पर है, अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गोरखपुर में एक IIT की स्थापना करने की दिशा में तत्काल निर्णय लेकर इस क्षेत्र के भविष्य को सँवारने में महत्वपूर्ण योगदान देने की कृपा करे। (इति)

Re: Need to conserve historical forts, sites and structures associated with Passi kings at various places in Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : माननीय सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के पासी बाहुल्य अवध क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सुहेलदेव पासी का साम्राज्य सीतापुर तक फैला हुआ था । पासी समाज के महाराजा बिजली पासी जी का किला लखनऊ, महाराजा सातन पासी जी का उन्नाव, महाराजा छीता पासी जी का सीतापुर, महाराजा सुहेलदेव पासी जी का बहराइच और लखनऊ को बसाने वाले लाखन पासी जी का किला आज भी विद्यमान है। इस में स्थित, सदियों पुराने, पासी समाज के राजा-महाराजाओं से जुड़े किले और टिले है। इनका ऐतिहासिक और कला-सांस्कृतिक महत्त्व अत्यधिक है। वर्तमान में ये स्थल उपेक्षा और संरक्षण अभाव के कारण तेजी से क्षरण की ओर अग्रसर हैं। सरकार से निवेदन है कि संबंधित मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि इन किलों एवं टिलों का तत्काल दस्तावेजीकरण और सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाए, रक्षा एवं पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हों, संरक्षण कार्य हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत किया जाए, स्थानीय समुदायों की भागीदारी को योजनाओं में सम्मिलित किया जाए, सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित कर स्थानीय आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए। यह पहल न केवल पासी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करेगी,बल्कि राष्ट्रीय पहचान को भी समृद्ध करेगी। (इति)

Re: Need to restart Mahalaxmi Mill, Beawar district, Rajasthan

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : मेरे संसदीय क्षेत्र के ब्यावर जिले में 1925 में स्थापित महालक्ष्मी मिल के मजदूरों को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है | लगभग 100 वर्ष पुरानी इस मिल के नवीनीकरण के प्रयास वर्ष 2008 में शुरू हुए थे और उसके उपरांत मशीनों की नीलामी और भूमि समतलीकरण के दो चरण पूरे भी हुए परन्तु तकनीकी अपग्रेड करके मिल का पुनर्निर्माण नहीं हो पाया और फिर इस मिल को अन्यत्र स्थापित करने पर भी विचार किया गया है | ब्यावर जिला कानपुर, कोलकाता और अहमदाबाद की तरह कपड़ों की मिलों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है| अत: आपके माध्यम से मेरी सरकार से यह मांग है कि महालक्ष्मी मिल के स्थापना शताब्दी वर्ष में इस स्थान में पारंपरिक व्यवसायिक गतिविधि को सम्मान देते हुए मिल का स्थानांतरण अन्य स्थल को न किया जाये और मिल का नवीनीकरण व उच्चीकरण करते हुए शीघ्रतातिशीघ्र मिल को फिर से ब्यावर जिले में ही शुरू किया जाये।

(इति)

Re: Need to develop historical places in Reasi district in Jammu Parliamentary Constituency

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनके प्रयास से जम्मू से श्रीनगर को रेल मार्ग से जोड़ा गया जो एक एतिहासिक कदम है, जबसे जम्मू-श्रीनगर रेल मार्ग का परिचालन हुआ है तबसे जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जिससे लोगों को रोजगार भी बढ़ा है | साथ ही मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र स्थित जम्मू में रियासी जिले में ऐतिहासिक स्थलों को प्रसाद योजना के माध्यम से विकसित करने की जरुरत है, जैसे कि –

1. रियासी जिला स्थित सुला पार्क है जो एक पर्यटक स्थल है, साथ ही 4 km की दूरी पर बारादरी दरिया घाट को विकसित करने की ज़रूरत है |
2. कांसी पट्टा दरिया घाट और सियाड़ बाबा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और टूरिस्ट प्लेस, आउटलेट माता मंदिर है
3. चिनकाह जहाँ बहुत ही पर्यटक आते हैं साथ ही क्न्थन टापू और थनपाल टापू फिर कोड़ी ब्रिज से होकर दोबारा पर्यटक सलाल स्थित प्राचीन शिव गुफा मंदिर के दर्शन करते हैं। इन जगहों को प्रसाद योजना के तहत विकसित करने किया जाय।

(इति)

Re: Need to expedite implementation of Mangaluru-Lakshadweep dedicated Jetty project

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): For decades, Mangaluru has served as the primary embarkation point for Lakshadweep, facilitating passenger and cargo movement. However, the absence of a dedicated jetty has led to congestion at Old Mangalore Port, hampering trade, tourism, and essential supplies to the islands. Recognizing this, the Ministry of Ports, Shipping, and Waterways approved 100% funding for a dedicated jetty and allied infrastructure for Lakshadweep at a cost of ₹65 crore, sanctioned on July 20, 2022. Yet, despite this approval, the project has not been awarded even after 18 months, and has now been placed in the 'deemed deferred category' under Sagarmala guidelines. This deferment is a serious setback to both Karnataka's coastal economy and Lakshadweep's developmental needs. The dedicated jetty is vital to ensure uninterrupted cargo and passenger movement, reduce port congestion, promote trade and cruise tourism, and strengthen maritime connectivity and national security in the Arabian Sea. I urge the Hon'ble Minister to urgently review this decision and take immediate steps to revive and expedite the implementation of the Mangaluru-Lakshadweep dedicated jetty project.

(ends)

Re: Need to extend benefits of Central Government Schemes to farmers of Delhi

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : दिल्ली के किसानों को केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता जिसके चलते वे केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं से आज तक वांछित हैं और दिल्ली के भूमिहीन किसानों को भारत सरकार ने सन 1975 मे जो भूमि दी थी उसका भी उनको आजतक मालिकाना हक नहीं मिला है । दिल्ली के किसान को मालिकाना अधिकार के साथ साथ साथ, केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलता, ना ही PMKUSUM योजना का लाभ मिलता और ना ही ऋण सुविधाओं, बीमा और अन्य केन्द्रीय योजनाओं का लाभ मिलता है। ये दिल्ली के किसानों के साथ अन्याय है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि दिल्ली के किसानों को मालिकाना हक और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले ऐसा प्रावधान जल्द जल्द किया जाना चाहिए।

(इति)

Re: Need to extend Delhi-Meerut Namo Bharat Corridor (Rapid Rail Transit System) up to Haridwar in Uttarakhand

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरठ को नमो भारत कॉरिडोर (रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम) की सौगात मिली है, जो दिल्ली के सराय काले खां से गाजियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर होते हुए मोदीपुरम तक फैला है। यह प्रदूषणमुक्त, वातानुकूलित यात्रा व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा व पर्यटन के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे मेरठ, दिल्ली का उपनगर सा बन गया है, संपत्ति मूल्य व विकास में भी तेजी आई है। यदि इस कॉरिडोर को मेरठ से हरिद्वार तक 130 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की होते हुए हरिद्वार तक पहुंचना केवल 2 घंटे में संभव होगा, जिससे ट्रैवल लागत व समय दोनों में भारी कमी आएगी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 50,000 वाहनों का रोजाना भार तथा वीकेंड पर हरिद्वार जाने वाले यात्रियों से 15,000 वाहन और बढ़ जाते हैं; यह भी घटेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। कॉरिडोर के विस्तार से मेरठ, रुड़की, हरिद्वार जैसे शिक्षा व औद्योगिक केंद्र और हरिद्वार व शुक्रताल जैसे तीर्थ स्थल सीधे जुड़ जाएंगे, रोजगार व पर्यटन को बल मिलेगा। मैं माननीय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर से अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकारों से परामर्श कर इस विस्तार पर विचार करें ताकि पूरा क्षेत्र प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू सके।

(इति)

Re: Non-supply of piped drinking water in Darbhanga district, Bihar

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा) : दरभंगा जिला में अधिकांश नागरिकों को नल से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण वे पानी पीने के लिए असुरक्षित जल का उपयोग करने पर मजबूर हैं। यह स्थिति गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को जन्म देती है,क्योंकि भूजल का अधिकांश हिस्सा पीने के लिए अनुपयुक्त है और इसमें प्रदूषण और विभिन्न हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। दरभंगा जिला में पानी की आपूर्ति की उचित व्यवस्था न होने के कारण, नागरिकों को पानी के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीने के लिए उपलब्ध भूजल में काफी समय से गुणवत्ता की कमी देखी जा रही है और यह जलजनित बीमारियों के फैलने का कारण बन सकता है। वर्तमान समय में तो लोग जल संकट को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं। यह स्थिति ना केवल जल संकट को बढ़ा रही है अपितु कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही, भूजल स्तर के गिरते स्तर को पुनः सुधारने के लिए भी जल पुनर्भरण योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाए। यह पहल ना केवल नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि समग्र विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अनिवार्य है।

(इति)

Re: Need to construct a building complex for police department in North East Delhi district

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक ढांचागत सुधारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

उत्तर पूर्वी दिल्ली देश की राजधानी का एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। चाहे 1992 के सांप्रदायिक दंगे हों या 2020 की हिंसक घटनाएँ, इनकी स्मृति आज भी जनमानस को झकझोर देती है। यह क्षेत्र दो राज्यों की सीमाओं से सटा होने के कारण अपराध नियंत्रण की दृष्टि से और अधिक जटिल हो जाता है।

इस संसदीय क्षेत्र में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था चार जिलों में विभाजित है, परंतु उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के पास पुलिस लाइन हेतु उपयुक्त भवन और परिसर उपलब्ध नहीं है। इससे कानून-व्यवस्था के संचालन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में, DDA की उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, वहाँ पुलिस लाइन के लिए एक समुचित परिसर एवं भवन का निर्माण कराया जाए। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों की त्वरित तैनाती संभव होगी और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण हेतु एक सुदृढ़ आधार केंद्र स्थापित किया जा सकेगा। (इति)

Re: Need to strengthen rail, road and air connectivity for regional development in Barak Valley, Assam

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Barak Valley in Assam is once again facing a grave connectivity crisis during this year's monsoon season. Relentless rainfall has triggered landslides, road subsidence, and infrastructure failures, disrupting all major routes—NH 6, NH 37, and the Lumding–Silchar railway line—and severely affecting road and rail connectivity. The recent collapse of the Harang Bridge on the Silchar–Kalain route, just weeks after a ₹137 crore repair, has completely cut off a vital link. Frequent landslides along NH 6 near Sonapur and Lumshnong, and fragile rail tracks continue to isolate the region. Air connectivity remains extremely limited and unaffordable, with insufficient flights and inadequate cargo facilities. As a result, people in the valley are facing high inflation in essential commodities, delays in medical treatment, severe disruption of student travel, and widespread economic distress. The region's recurring isolation highlights the urgent need for structural, long-term solutions, including robust road, rail, and air connectivity. The current state of affairs is a humanitarian, economic, and logistical emergency. This House must take urgent note of the situation and ensure that Barak Valley receives the focused attention and investment it has long been denied.

(ends)

Re: Need to establish cold storage and mini on-farm processing units in Peddapalli region in Telangana

SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM (PEDDAPALLE): I wish to draw the attention of this House to the urgent need for strengthening cold storage infrastructure for vegetable farmers in the Peddapalli region of Telangana. Farmers cultivating perishable crops like chillies, bananas, and tomatoes are facing significant post-harvest losses due to the lack of proper storage and preservation facilities. Despite good yields, the absence of cold storage leads to distress selling, spoilage, and financial losses, particularly among small and marginal farmers. There is an immediate need for the construction of decentralised cold storage units, including solar-powered cold chains to ensure sustainability and reduce dependence on grid electricity in rural areas. I also urge the government to support the establishment of mini on-farm processing units, which can extend shelf life, reduce wastage, and improve market value. Financial and technical assistance through schemes under the Ministry of Food Processing Industries and Ministry of Agriculture should be extended to Farmer Producer Organisations (FPOs) and rural entrepreneurs in Peddapalli. I request the Government to treat this as a high-priority intervention for agricultural resilience and rural income enhancement. Thank You. (ends)

Re: Need to expedite completion of work to widen the stretch of NH No. 966 between Olavakkode and Thanavu in Kerala

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Many deep and large potholes on Olavakkode-Thanavu road of National Highway No.966 are creating heavy road blocks / traffic jams and accidents leading to deaths for the last several months. The vehicular movements during the rainy season are a daunting task on this stretch due to deep potholes. Long traffic jams from New Bridge to Puthuppariyaram Industrial Estate is a regular phenomenon during day and night. The widening work of National Highway 966 has been stopped just 250-300 mtrs before Thanavu junction. This has created a bottleneck shape there. Many accidents occurred because of the incompletion of widening work near Thanavu junction. Accidents are a regular phenomenon, as well as traffic jams due to sudden road width reduction. It is necessary to widen the stretch between Olavakkode and Chandra Nagar in Palakkad from two lanes to at-least four lanes as this stretch has huge traffic volume as all the vehicles towards Tamil Nadu and Karnataka have to pass through this stretch. Therefore, I urge upon the Government to resolve these issues of potholes, complete the incomplete widening work before Thanavu junction and expand from two lanes to four lanes between Olavakkode and Chandra Nagar - all concerning National Highway 966. (ends)

Re: Need for a comprehensive plan to develop Raja Ravi Varma College of Fine Arts in Kerala as Centre of Excellence

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I would like to bring to the attention of the Government the significant potential and cultural importance of the Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara, Kerala. This historic institution, named after one of India's greatest artists, has played a vital role in nurturing generations of talented artists and preserving the country's rich artistic heritage. In recognition of its contributions, I urge the Government to consider a comprehensive development plan to elevate the college into a Centre of Excellence. This may include: – Upgradation of infrastructure and academic resources, – Introduction of postgraduate and doctoral-level programs, – Establishment of a national gallery and artist residency programmes, and – Integration with national institutions under the Ministry of Culture or the Ministry of Education. Such a move would not only honour the legacy of Raja Ravi Varma but also provide a major boost to fine arts education and cultural promotion in the region and beyond. I request the concerned Ministry to take positive steps towards realising this vision.

(ends)

Re: Conservation of Wainganga river in Maharashtra

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया संसदीय क्षेत्र में वैनगंगा नदी पर मंडरा रहे गंभीर संकट की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह नदी आज प्रदूषण और अवैध रेत खनन, दोनों से त्रस्त है। नाग नदी से आने वाले गंदे, जहरीले पानी के कारण वैनगंगा का जल गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है, जो न केवल जलजीवों के जीवन के लिए खतरनाक है, बल्कि इस पानी का उपयोग करने वाले नागरिकों, मवेशियों और किसानों के स्वास्थ्य एवं आजीविका को भी प्रभावित कर रहा है। प्रदूषित जल से फसलें प्रभावित हो रही हैं और मिट्टी की उर्वरता घट रही है। दूसरी ओर, नदी तटों पर हो रहा अनियंत्रित अवैध रेत खनन, जलधारा, पारिस्थितिकी तंत्र और मछली पालन को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में मेरा सरकार से प्रश्न है— क्या केंद्र सरकार एक स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) कराएगी? क्या अवैध रेत खनन पर रोक के लिए आधुनिक निगरानी तकनीकों को अपनाया जाएगा? क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से विशेष सहायता मांगी है? मैं सरकार से वैनगंगा नदी के संरक्षण हेतु ठोस कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

(इति)

Re: Need to ensure scientific and technology based construction of 6-laning project on NH No. 66 in Kerala

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): The 6-laning project of NH 66 in Kerala is plagued by safety issues, environmental damage and severe delays. Unscientific construction on weak, waterlogged terrain, such as at Kooriyadu in Malappuram, has led to repeated collapses even before completion of project. High embankments on reclaimed paddy fields and disrupted water flow have worsened flooding and collapse risks. Cracks observed in completed sections across Kasaragod, Kannur, Kozhikode, Malappuram, and Thrissur districts reflect poor construction quality by the companies involved. Reports cite unsafe soil extraction and unscientific hillside cutting, raising landslide fears. Construction mismanagement and sluggish progress, especially on the Azhiyur–Vengalam stretch of Kozhikode district, have worsened the situation. I request Hon'ble Minister to address these issues, ensure accountability and expedite project completion.

(ends)

Re: Railway related issues of Kheri Parliamentary Constituency

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : मैं सरकार का ध्यान अतिमहत्वपूर्ण विषय लोकसभा खीरी में रेल परिचालन व संबंधित मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजादी से अब तक नई दिल्ली, अमृतसर, मुंबई जैसे शहरों के लिए सीधा रेल परिचालन नहीं है। आज देश में राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, वंदे भारत जैसी ट्रेन लगभग सभी संसदीय क्षेत्र में परिचालन में है। ऐसे में लोकसभा खीरी वासियों की निगाहें बराबर सरकार की ओर है। सीतापुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन का विस्तार भी मैलानी जंक्शन तक करने से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। मैलानी जंक्शन से नानपारा जंक्शन 171 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। यह छोटी लाइन है। 14 हाल्टों से युक्त रेल मार्ग सफर करने में साढ़े 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इस रेल मार्ग से सफर करने वाले लाखों लोग व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन के लिए इस पर आश्रित हैं। इसे बड़ी रेल लाइन में बदलने की सख्त जरूरत है। अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से लखीमपुर से डाइरेक्ट नई दिल्ली, अमृतसर व मुंबई जाने वाली ट्रेन का मैलानी जंक्शन तक विस्तार और मैलानी से नानपुरा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में तब्दील करने की मांग जनहित में करता हूँ। इससे क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा व सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी।

(इति)

Re: Need to restore stoppage of trains withdrawn during covid-19 pandemic in Ongole Parliamentary Constituency

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): During the COVID-19 pandemic, several train stoppages in the Guntur Division of South Central Railway were withdrawn as a temporary measure. However, even after the resumption of normal operations post-COVID-19, these stoppages have not been restored. This has caused severe inconvenience to the people of Guntur Division, particularly in my Ongole Parliamentary Constituency. Daily commuters, farmers, students, and traders are facing immense hardship due to the lack of accessible rail services. The non-restoration of train stoppages is adversely affecting the economic and social activities in the region. I urge the Hon'ble Minister of Railways to take immediate steps to restore all the withdrawn train stoppages in Guntur Division at the earliest, to alleviate the difficulties faced by the people and ensure seamless connectivity in the region.

(ends)

Re: Need to ensure passenger and aircraft safety through robust aviation measures

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): There has been a disturbing rise in incidents of technical snags and emergency landings involving commercial aircraft in recent months. These repeated occurrences raise serious concerns about the maintenance standards, safety protocols, and preparedness of airline operators. Passengers are being subjected to increasing levels of risk, undermining public trust in the safety of air travel. In addition, the virtual monopoly of two major airlines—Indigo and Air India—has led to a lack of competitive checks in the aviation sector. This has contributed to steep increases in airfare and deteriorating service standards, including frequent delays and overbookings. Recent near-miss incidents and mid-air malfunctions have made it clear that ensuring passenger safety can no longer be treated as a routine compliance matter but requires urgent and systemic reform. I urge the Ministry of Civil Aviation to immediately strengthen technical audits, enforce strict safety inspections, and establish accountability for recurring failures. Further, steps must be taken to open the sector for broader competition and to regulate airfare in public interest.

(ends)

Re: Need to restart excavation of Tungsten in Degana area in Nagaur district, Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : खनन मंत्री जी का ध्यान मेरे राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र के रेवत हिल क्षेत्र में टंगस्टन खनन की वर्तमान स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा रेवत हिल क्षेत्र में टंगस्टन एवं लिथियम सहित नियोबियम-टैंटलम और टिन जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की पुष्टि की गई है। वर्तमान में डेगाना क्षेत्र में खनन की स्वीकृति नहीं है,लेकिन G3 और G2 चरणों में किए गए सर्वेक्षण में टंगस्टन: 13.39 मिलियन टन,लिथियम: 6.33 मिलियन टन (@400 ppm कट-ऑफ) ,नियोबियम-टैंटलम: 16.42 मिलियन टन ,टिन: 0.15 मिलियन टन की उपलब्धता के प्रमाण मिले हैं। अत: डेगाना क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता एवं मात्रा में दुर्लभ खनिज मौजूद हैं, जिनका यदि व्यावसायिक खनन प्रारंभ किया जाए, तो इससे न केवल स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की खनिज आत्मनिर्भरता भी सशक्त होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन खनन को शीघ्र पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए,इस दिशा में खनन पट्टों की स्वीकृति, एवं निवेश प्रोत्साहन हेतु आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएं तथा नागौर जिले को एक खनिज आधारित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु विशेष योजना बनाई जाए। (इति)

Re: Creation of 'Bheel Pradesh'

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : राजस्थान-मध्यप्रदेश-गुजरात-महाराष्ट्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के भील समुदाय की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, आजादी के बाद समान संस्कृति-पहचान वाले क्षेत्र को विभिन्न राज्यों में विभाजित कर दिया गया, जिससे यहां के आदिवासियों की विशिष्ट पहचान खत्म हुई है व क्षेत्र का समुचित विकास नही हुआ है, उक्त भीलप्रदेश का क्षेत्र निम्नानुसार है:-

1. राजस्थान:- डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली, राजसमंद, चित्तोड़गढ़ कोटा एवं बांरा जिले (28 लाख 05 हजार 948 आदिवासी जनसंख्या)
2. गुजरात:- बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, वडोदरा ग्रामीण, नर्मदा, भरूच, सुरत, तापी एंव नवसारी, जिले (34 लाख 41 हजार 945 आदिवासी जनसंख्या)
3. मध्यप्रदेश:- रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर एवं खंडवा जिले। (46 लाख 19 हजार 68 आदिवासी जनसंख्या)
4. महाराष्ट्र:- नंदुबार, धुले, जलगांव, नासिक, पालघर एवं ठाणे जिले (18 लाख 18 हजार 792 आदिवासी जनसंख्या)

1913 में गोविन्द गुरू के नेतृत्व में मानगढ़ पर लाखो भील एकत्र हुए थे जिनपर अंग्रेजों-रजवाड़ो द्वारा गोलिया चलाने से 1500 से अधिक आदिवासी मारे गए थे, साथ ही भीलप्रदेश के लिए विभिन्न जन-आन्दोलनों, सामाजिक-राजनैतिक संगठनों, व्यक्तियों द्वारा हमेश मांग उठाई है। राजस्थान-गुजरात-मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर एक भील प्रदेश के निर्माण की आवश्यकता है।

(इति)

माननीय सभापति : मैं चाहता हूं कि आप सभी सदस्यगण स्वयं में समीक्षा करें कि हंगामा किसके हित में है और इस हंगामे का लाभ किसे होगा? कम से कम जनता को तो इस हंगामे का लाभ नहीं मिलेगा। आपको जनता ने अपनी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में बात करने के लिए भेजा है।

… (व्यवधान)

(1405/KDS/SMN)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : अभय कुशवाहा जी, आप सदन को बाधित कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि इससे जनता को लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है? हैबी ईडन जी, मेरी बात सुनिए। अगर सदन की कार्यवाही को बार-बार आप लोग स्थगित करेंगे, तो it would not be any achievement. यह कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए यह भारी चिंता का विषय है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। इस तरह से रोज-रोज व्यवधान करना ठीक नहीं है। दो सौ माननीय सदस्यों के प्राइवेट मैंबर बिल्स हैं। इन बिल्स का महत्व उतना ही है, जितना सरकार के द्वारा लाए गए बिलों का होता है। आज का दिन आपके लिए है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : स्पीकर साहब ने सुबह प्रश्नकाल में आपसे कहा कि हम इस सदन को सुचारू रूप से चलाने की पहल करेंगे। आपके जो भी विषय हैं, उसके लिए हम सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे। आपके साथ बैठेंगे, परस्पर सहमति करेंगे, एक रास्ता निकालेंगे।'

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : चेयरमैन सर, आज का बिल गोवा विधान सभा में एसटी को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित है।… (व्यवधान) लेजिस्लेटिव बिजनेस गोवा विधान सभा में अनुसूचित जनजाति को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। … (व्यवधान) विपक्ष के लोगों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे अनुसूचित जनजाति के भी खिलाफ हैं? यह महत्वपूर्ण बिल है। … (व्यवधान)

सर, यह बिल गोवा विधान सभा में अनुसूचित जनजाति को रिप्रेजेंटेशन देने से संबंधित है। कृपया आप मुझे अलाऊ करिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी एक विषय उठा रहे हैं कि गोवा के एसटी लोगों को रिजर्वेशन देना है। कई दिनों से यह बिल एजेंडे में लगातार आ रहा है। यदि आपकी सहमति हो, तो उस पर आज चर्चा कर लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण प्राइवेट मैंबर बिजनेस है और दो सौ माननीय सदस्यों के प्राइवेट मैंबर बिल्स हैं, जिनको आज 'ले' करना है। प्राइवेट मैंबर बिजनेस पर चर्चा होनी है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज केवल आपका दिन है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Friday is reserved only for Private Members' Business. यह आपका बिल है और यह काफी महत्वपूर्ण बिल है। इस पर पूरे सदन के सदस्य चर्चा करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जय प्रकाश सिंह जी, अमर सिंह जी, बैन्नी बेहनन साहब, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये वैल को खाली करें, ताकि हम सभी को प्राइवेट मैंबर बिजनेस के लिए अलाऊ करें। दो सौ माननीय सदस्यों को प्राइवेट मैंबर बिल्स 'ले' करने हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, स्पीकर साहब ने आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई। वर्षा जी, कृपया सुन लीजिए। उन्होंने आज कहा कि हम सरकार के प्रतिनिधियों व विपक्ष तथा सभी पार्टीज़ के समस्त सदस्यों को बुलाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी और राज्य मंत्री जी, एलओपी से मिले। यह डेडलॉक कैसे खत्म होगा? चेयर चिंतित है, पूरा देश चिंतित है कि आखिर इस सदन में क्या हो रहा है?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : देश की जनता को यह जानने का हक है कि इस सदन में क्या हो रहा है। आप अपने संसदीय क्षेत्रों में शनिवार व रविवार को जाएंगे। आजाद जी, आप अपने क्षेत्र की जनता से पूछिएगा कि जनता क्या चाहती है? क्या वह सदन में आपको हंगामा करते देखना चाहती है?

… (व्यवधान)

(1410/CS/RP)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : आप जनता के दु:ख और तकलीफों के बारे में सदन में चर्चा करें, वे आपसे इसकी अपेक्षा रखते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके रिकॉर्ड में क्या जाएगा?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : धर्मेन्द्र जी, आप शनिवार, रविवार को अपने क्षेत्र के लोगों से पूछिएगा कि वे आपको यहाँ बोलते हुए देखना चाहते हैं, आपको प्राइवेट मैंबर बिजनेस में भाग लेते देखना चाहते हैं या आपको केवल हंगामा करते हुए देखना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : जब सरकार उन विषयों पर संज्ञान ले रही है। देश और आम जन की…

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप हंगामा करके देश की जनता का अहित कर रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सब अपनी-अपनी जगह पर जाएं और सदन की कार्यवाही चलाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अभय जी, सदन की कार्यवाही चलावाने में सहयोग करें।। सभी के प्राइवेट मैंबर बिल्स हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप जो आचरण कर रहे हैं, वह इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह वही सदन है, जिसमें देश की जनता ने उनसे जुड़े हुए विषयों पर गंभीर चिंतन-मनन होते हुए देखा है। स्वस्थ सकारात्मक संवाद के माध्यम से उनकी परेशानियों का समाधान निकलते देखा है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से जनहित में कानून बनते देखा है। यह सदन ऐतिहासिक है। यह सदन इस बात का गवाह रहा है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरा आग्रह है कि इस सदन ने आपको देश में जनहित के कानून बनाते हुए देखा है। आप लोग इस वेल को वैकेट करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप सब अपनी-अपनी जगह पर जाएं और सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं असमर्थ हूँ कि जब सरकार प्रत्येक विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, देखिए, सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : स्पीकर साहब ने भी पहल की है। उन्होंने आज सभी दलों के नेताओं के साथ ऑल पार्टी मीटिंग की है और एक रास्ता निकाला है। जब सरकार सदन के अंदर, सदन के बाहर आश्वस्त कर रही है कि वह हर विषय पर नियमानुसार चर्चा करने के लिए तैयार है, तो फिर इस गतिरोध का क्या कारण है?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप मेरी बात सुनिए। आप सरकार से जवाब माँग रहे हैं। आप सरकार से जवाब चाहते हैं, तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं अर्जुन राम मेघवाल जी से कह रहा हूँ कि आप जवाब दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, मैं तैयार हूँ। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ... (व्यवधान) यह अनुसूचित जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण बिल है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी, जवाब देने के लिए तैयार हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कस्वां जी, शैलजा जी, आप जवाब माँग रहे हैं। मंत्री जी, जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर सदन में व्यवधान क्यों उत्पन्न हो रहा है?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर यह व्यवधान क्यों उत्पन्न हो रहा है?

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, आप इस बिल पर चर्चा कराइए।... (व्यवधान) आप चर्चा कराइए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को बाधित मत कीजिए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और मैं आपको अलाऊ करने के लिए तैयार हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह पूरा सप्ताह, पूरा वीक आपके हंगामे के कारण वाशआउट हो गया है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आखिर देश की जनता की आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, लेकिन आप इस सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ कि आप इस सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाएँ। आज प्राइवेट मैंबर बिजनेस है। प्राइवेट मेंबर बिजनेस यानी फ्राइडे बहुत महत्वपूर्ण होता है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अरविन्द सावंत जी, लगभग 200 माननीय सदस्यों को अपने-अपने प्राइवेट मैंबर बिल को रखना है। आपको भी ले करना है, अन्य सभी माननीय सदस्यों को भी ले करना है। सदन इस तरह से नहीं चलता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब प्राइवेट मेंबर बिजनेस पर सहयोग करें।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सुप्रिया जी, आप इन लोगों से आग्रह कीजिए। राहुल गाँधी यहाँ नहीं हैं। हैबी ईडन साहब, आप लीडर के रूप में आग्रह करें। हुड्डा साहब, आपसे आग्रह है। मणिक्कम जी, आप इन लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि ये लोग अपनी सीट्स पर आएं और प्राइवेट मैंबर बिजनेस पर चर्चा करने के लिए तैयार हों। आप सभी वरिष्ठ लोग हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 28 जुलाई, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1413 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 28 जुलाई 2025 / 6 श्रावण 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।